एमओएचयूए और हडको ने 8 नवम्बर, 2025 को

अर्बन इन्वेस्ट विंडो– यूआईविन

का शुभारम्भ किया

शहरों/यूएलबी के विकास के लिए एक समग्र समाधान के रूप में

हडको hudco A NAVRATNA CPSE

मुख्य उद्देश्य:

भारत सरकार की योजनाओं और व्यापक, सुरक्षित क्षेत्र-आधारित विकास—क्लस्टरों/शहरों—के सफल कार्यान्वयन के लिए यूएलबी को एक मंच और सहयोग प्रदान करना।

अपेक्षित परिणाम :

शहर →

- **C** कम कार्बन और संसाधन-कुशल शहरी विकास
- **I** आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निवेश के लिए तैयार शहर/क्लस्टर
- **T** सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और शहरी शासन
- **I** समावेशी आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन - शहरी अर्थव्यवस्था/जीडीपी में सुधार
- **E** शहरी पारिस्थितिकी और विरासत का संरक्षण
- **S** सतत, सुरक्षित और सुदृढ़ शहरी पर्यावरण

मुख्य कार्यात्मक वर्टिकल्स - यूआईविन

क्षमता निर्माण

- परिसंपत्ति पहचान, इन्वेंट्री और रजिस्टरr
- परिसंपत्ति के मूल्य और प्रदर्शन को अधिकतम करना
- संसाधन पहचान, ऋण प्रबंधन फ्रेमवर्क
- उधार लेने की सीमाएँ, ऋण-सेवा क्षमता
- PPP परियोजना सहायता

परियोजना पहचान और निर्माण

- परियोजना की पहचान, संकल्पना और कार्यान्वयन के लिए सहयोग
- डीपीआर, व्यवहार्यता अध्ययनों आदि की तैयारी
- निजी भागीदार के साथ जुड़ना
- परियोजना संरचना

वित्तीय और पूंजी बाज़ारों तक पहुँच

- अपने संसाधनों को मज़बूत करना
- बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और FDI तक निवेश सुविधा की पहुँच
- निजी फंड (पीपीपी) और ऋण (हडको, NaBFID, एनआईआईएफ)
- क्रेडिट रेटिंग में सहायता
- म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने में सहयोग

परिसंपत्ति मुद्रीकरण और परिसंपत्तियों का प्रबंधन

- यूएलबी /शहरों की मौजूदा संपत्तियों की मैपिंग
- परिसंपत्ति रजिस्टर का निर्माण और डिजिटलीकरण
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण की रणनीति
- परिसंपत्ति मुद्रीकरण ढाँचा

प्रमुख चुनौतियां

द्वितीयक शहरों में सतत विकास को धीमा करने वाली प्रमुख बाधाएँ

वित्तीय बाधाएँ

नए UCF प्रोजेक्ट्स के लिए 50% मार्केट फ़ाइनेंसिंग ज़रूरी है।

- कम साख: छोटे ULB के पास म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए ज़रूरी रेटिंग की कमी होती है।
- :निर्भरता: राज्य हस्तांतरणों पर अत्यधिक निर्भरता; आंतरिक राजस्व सृजन कमज़ोर।
- रिकवरी गैप: सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाने और वसूलने की सीमित क्षमता

इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप

31% शहरी परिवारों तक पाइप से पानी की पहुँच नहीं है।

- सीवेज की कमी::
- जल आपूर्ति की कमी:
- सेवाओं में अंतराल: आवासों की अपर्याप्त उपलब्धता और अपशिष्ट प्रबंधन की खराब व्यवस्था।.
- अपर्याप्त नियोजन
- अनुचित कनेक्टिविटी

शासन और क्षमता

तकनीकी कर्मचारियों की गंभीर कमी

- ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण: नियोजन में शहर-स्तर की सीमित भागीदारी;
- कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे: समग्र योजना के बजाय खंडित, 'प्रोजेक्ट-केंद्रित' कार्यान्वयन।
- कैडर-आधारित पेशेवरों की कमी
- अनुचित O&M: बजट का कम आबंटन,

यूआईविन –शहर के समग्र विकास में हस्तक्षेप

- बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण
- औद्योगिक और वाणिज्यिक विस्तार-विकास
- एकत्रीकरण के माध्यम से संस्थागत वित्त तक पहुँच
- भूमि के मूल्य और नगरपालिका राजस्व में वृद्धि
- रोज़गार सृजन और कौशल विकास

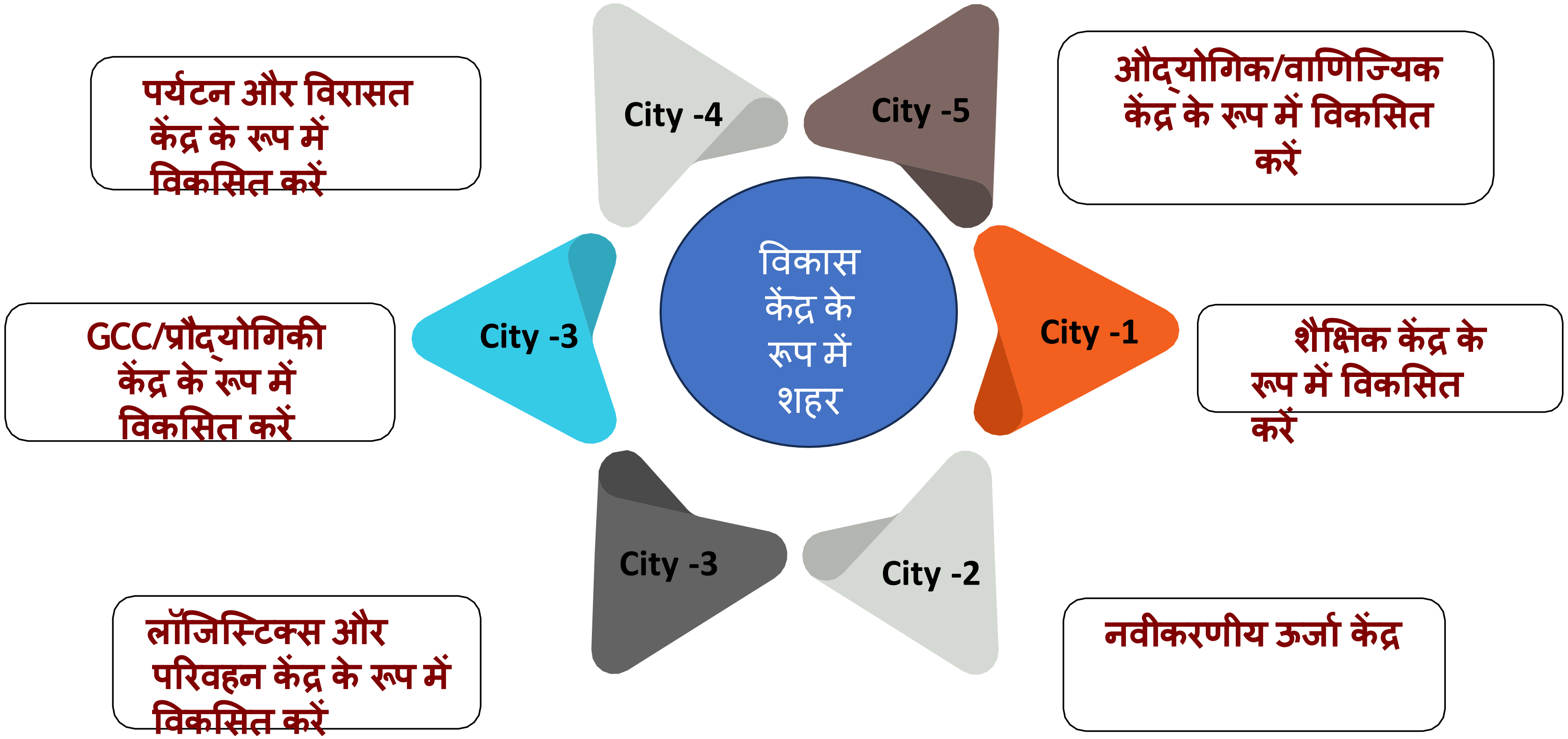

शहर का व्यापक क्षेत्र-आधारित विकास (ABD)

यूआईविन का प्रभाव

- मुद्रीकरण हेतु परिसंपत्ति पुनर्चक्रण
- सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल
- निजी निवेश – PPP, HAM, BOT, BOOT आदि
- पूल किया गया नगरपालिका बॉन्ड
- भूमि मूल्य अधिग्रहण (LVC) + बॉन्ड वित्तपोषण हाइब्रिड उपकरण
- नगरपालिका अवसंरचना SPV (रिंग-फेन्स्ड मॉडल)
- हरित एवं जलवायु नगरपालिका बॉन्ड
- मिश्रित वित्त तंत्र
- राजस्व प्रतिभूतिकरण मॉडल
- बहुपक्षीय वित्तपोषण (क्षेत्र-विशिष्ट)
- घरेलू कम लागत वाले फंड जैसे पेंशन, LIC वगैरह।
- वैकल्पिक निवेश कोष

यूआइडविन का भारत सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण

शहरी आर्थिक क्षेत्र (CER)

7 CER (बजट 2026–27)

₹5,000 करोड़ प्रति CER (5 वर्ष)

सुधार-आधारित संवितरण;

हाई-स्पीड रेल से संरेखित

शहरी चुनौती कोष (UCF)

₹1 लाख करोड़ का भारत सरकार का सहयोग (5 वर्ष) | ₹4 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य

25% भारत सरकार | 50% बाज़ार | 25% राज्य/ULB

विकास केंद्र | पुनर्विकास | जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (WSS)

16वें वित्त आयोग का

विशेष अनुदान: 56,100 करोड़ रुपये। 10 लाख से 40 लाख की आबादी वाले शहरों में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली का विकास।

म्युनिसिपल बॉन्ड्स

₹3,800 करोड़ जारी किए गए (16 शहर) बजट 2026–27: ₹1,000 करोड़ से अधिक के इश्यू के लिए ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन

शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कोष (UIDF)

NHB के माध्यम से ₹10,000 करोड़ प्रति वर्ष।

PSL की कमी से वित्तपोषित - राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं।

टियर 2 और 3 की वित्तपोषण संरचना के लिए।

अमृत 2.0

स्मार्ट सिटी

पीएमएवाई (U)-2.0

एसबीएम

परिणाम: सुधार-आधारित वित्तपोषण | बाजार उत्तोलन | क्षेत्रीय आर्थिक परिवर्तन

यूआईविन के अंतर्गत कार्यनीति

एक व्यापक 'क्षेत्र-आधारित विकास' (ABD) को अपनाना – परियोजना की अवधारणा से लेकर वित्तीय समापन और कार्यान्वयन तक।

A. UiWIN के साथ शहरों और राज्यों को जोड़ना

- स्मार्ट सिटी SPVs/ULBs/शहर सरकारों को शामिल करके, शहरों में ABD की संभावनाओं की पहचान करना;
- UiWIN के साथ कार्य करने के प्रति राज्य सरकार और शहर की तत्परता और प्रतिबद्धता का मूल्यांकन

B. क्षेत्र की पहचान (रिंग-फेंसिंग)

- ABD के लिए शहर के भीतर एक परिभाषित और आपस में जुड़ा हुआ क्षेत्र चुनना
- प्रीसिंक्ट सिटी' या 'शहर के भीतर शहर' के दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक और एकीकृत विकास

यूआईविन के अंतर्गत कार्यनीति

एक व्यापक 'क्षेत्र-आधारित विकास' (ABD) को अपनाना – परियोजना की अवधारणा से लेकर वित्तीय समापन और कार्यान्वयन तक।

C. ABD के अंतर्गत अवसंरचना आवश्यकताओं का आकलन

- शहर की आय और व्यय प्रोफ़ाइल।
- शहर की उधार लेने की क्षमता।
- मौजूदा शहरी संपत्तियाँ।
- चल रही और पूरी हो चुकी परियोजनाएँ।
- विचाराधीन परियोजनाओं के लिए SPV को शामिल करते हुए गैप विश्लेषण।
- केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन।
- **बिना किसी वित्तीय दबाव के, बैंक-योग्य, सतत और लागू करने योग्य परियोजनाओं के लिए शहर की अवशोषण क्षमता का आकलन।**

➢ **मौजूदा सरकारी कार्यक्रमों का अभिसरण**
➢ **संभावित राजस्व स्रोतों की पहचान और संवर्धन**

यह कैसे किया जा सकता है?

UiWIN के मूल सिद्धांत

क्षेत्र-आधारित विकास के लिए ULB, शहर, राज्य आदि के बीच आम सहमति बनाना।

राज्य की ओर से अधिदेश/प्रतिबद्धता

सिटी और हडको के बीच MoU

हडको में आईएसयू द्वारा बैंकेबल प्रोजेक्ट्स का निर्माण

• CDP, CIP, DPRs, परिसंपत्ति रजिस्टर आदि की तैयारी

•शहर द्वारा DPRs की स्वीकृति.

•भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, राज्य अनुदानों और अन्य राजस्वों का एकीकरण।

•बहुपक्षीय/घरेलू वित्तपोषण (PPP, बॉन्ड, पूल फाईनेंसिंग आदि) के माध्यम से निवेश सुविधा।

•वित्तीय समापन और कार्यान्वयन।

•प्रमुख अधिकारियों की क्षमता निर्माण।

फ्रेमवर्क संरक्षक

- एमओएचयूए
- राज्य

संचालन समिति

संरक्षक + सीएमडी, हडको + राज्य/शहर प्रशासन/SPVs

परिवर्तन साझीदार

हडको

- बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान (WB, ADB, IFC, आदि)
- बैंक/वित्तीय संस्थान/NIIF
- शैक्षणिक संस्थान (NIUA, IIMs, IITs)
- परिसंपत्ति प्रबंधन और मुद्रीकरण विशेषज्ञ
- परियोजना प्रबंधन और DPR विशेषज्ञ
- शहरी वित्त विशेषज्ञ

कार्य संरक्षक

शहरी इन्फ्रा के विकास का दायित्व, स्वामित्व और समर्थन

संचालन समिति

विभिन्न चरणों पर अनुमोदन

परिवर्तन साझीदार

- परियोजना की योजना
- वित्तीय समापन
- परियोजनाओं का निष्पादन एवं निगरानी
- परिसंपत्ति रजिस्टर
- परिसंपत्ति की पहचान एवं मुद्रीकरण
- क्षमता निर्माण

कार्य योजना

- शहर की पहचान और SCM SPVs के साथ चर्चा
- राष्ट्रीय/राज्य/ULB स्तर की कार्यशालाएँ, SPV को शामिल करते हुए
- ABD के लिए राज्य की प्रतिबद्धता और MoU निष्पादन
- व्यापक ABD योजना की तैयारी
- ABD योजना: जल, SWM, सड़क, गतिशीलता, रियल एस्टेट, आर्थिक विकास गलियारा आदि।
- पात्र परियोजना का वित्तीय समापन
- निवेश सुविधा
- म्युनिसिपल बांड
- परिसंपत्ति रजिस्टर और मुद्रीकरण
- शहरों में विशेषज्ञों की टीम की तैनाती
- उपर्युक्त सभी गतिविधियों में प्रमुख ULB अधिकारियों की क्षमता निर्माण

चरण

धन्यवाद

विकसित भारत के लिए शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर का वित्तपोषण

मुख्यालय :

हडको भवन, कोर-7-A, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003